LOK SABHA

Tuesday, March 24, 1964/Chaitra 4, 1886 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Forest Resources

\+

*714. **Shri Vishram Prasad:**
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri M. Rampure:
Shri Koya:
Shri Imbichibava:
Shri A. K. Gopalan:
Shri P. Kunhan:
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken any project to compile a complete record of forest resources to plan the establishment of new wood-based industries;

(b) whether Government have undertaken a pre-investment survey of forest resources for these wood-based industries;

(c) when this survey will be completed; and

(d) whether any foreign assistance monetary or technical has also been accepted and, if so, the name of the foreign country?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). The Government of India has on hand a project entitled "Pre-investment Survey of Forest Resources", which aims at conducting pre-investment surveys of forest resources over areas aggregating about 11,500 square miles.

(c) The Survey is expected to take about 3½ Years for completion after it is started.

(d) Yes. From the United Nations Special Fund.

श्री विश्राम प्रसाद : हमारी इंडस्ट्रीज के लिये जो लकड़ी की कमी होती है, इस सर्वे से कहां तक हम उस कमी को दूर कर सकेंगे, कहां तक हम सैल्फ-साफिशेंट हो सकेंगे लकड़ी के मामले में तथा कहां तक फर्दर प्रोग्रेस हम करेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह: भारत के उद्योगों को जितनी किस्म की लकड़ियों की जरूरत होती है, केवल आज ही की उनकी आवश्यकताओं के आधार पर यह कहना कि हम स्वावलम्बी हो सकेंगे, इतना मुनासिब नहीं होगा । कारण यह है कि रोज रोज उनकी लकड़ी की मांग बढ़ती जाती है । इस लिये हम कोशिश यह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस सर्वे के आधार पर बन के धन को बढ़ाया जाय ताकि इनकी मांग को पूरी करने की कोशिश की जा सके ।

श्री विश्राम प्रसाद : जरूरत के मुताबिक लकड़ी मिल सके, उसके लिये

क्या कोई रिसर्च या एफोरेस्टेशन की स्कीम सरकार के पास है ताकि कमी को पूरा करने के लिये भारत में प्लाटेशन हम कर सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : इस वक्त ऐसी कई एक योजनायें हैं । जैसे कागज उद्योग है उसके लिये युकलिपटस वगैरह के, या दिया सलाई के उद्योग के लिए सलाई वगैरह के जंगल लगाये जाते हैं । कड़ी लकड़ी के लिये सखुआ और सागवान के लगाये जाते हैं । उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार जंगल बढ़ाने की बात चल रही है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : वन सम्पदा का सर्वे कराने के साथ साथ क्या इस ओर भी आपका ध्यान गया है कि वनसम्पदा को बड़ी बेरहमी के साथ काटा जा रहा है ? वन-सम्पदा को बेरहमी के साथ कटने के से बचाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : इसकी काफी रोकथाम की जाती है । माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जहां से वह खुद आते हैं, वहां जंगल में कोई ऐसे हथियार ले जाने की मुमानियत कर दी गई थी जिससे जंगल बेरहमी से काटे जा सकते हों और बिना इजाजत ऐसा नहीं किया जा सकता था । लेकिन साथ साथ वह इसे भी मानेंगे कि जो जरूरत है लोगों की खास कर जंगल के नजदीक रहने वाले लोगों की, उसको देखते हुए ही जंगलों की रक्षा की बात बढ़ाई जा सकती है और वैसा किया जा रहा है ।

Shri H. P. Chatterjee: According to our planners in the Third Plan we require 4·5 million tons of industrial wood annually which will increase to 9·5 million tons by 1975. This is mentioned in the Third Plan. We also require 60 million tons of fire wood, which is equal to 400 million tons of cow-dung which we burn annually, which will increase to 100 million tons annually by 1975. The difference from the present annual output is so very great. What the Minister proposes to do in the mater to meet all these requirements? How much he gets annually now and how much he expects to increase every year?

Mr. Speaker: Not so many questions in one supplementary.

Dr. Ram Subhag Singh: Even now we are short of both timber and fuel wood. We are importing good quality timber in large quantities from the neighbouring countries of Nepal and Burma. Regarding fuel wood, as the hon. Member himself has stated, we are burning cow dung. All these needs are going to be tackled through various other sources. In regard to fuel, power may also be utilised and is being utilised in urban areas. So is the case in regard to timber etc. because concrete poles etc. are also being manufactured. But I do not want to depend on that. It is precisely with a view to tackling timber and fuelwood requirements and to meet the increasing demands that a new afforestation policy has been launched and everywhere forests are being replanted.

डा० गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि जहां तक इस देश में वन सम्पदा का सम्बन्ध है, वहां तक मध्य प्रदेश का एक खास स्थान है । जो अनुसंधान हो रहा है, उसमें क्या इस बात का भी अनुसंधान किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जंगलों को देखते हुए, वहां की लकड़ी को देखते हुए वहां पर इस प्रकार के कौन से उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : एक न्यूजप्रिंट का कारखाना वहां पर बना है जिसका नाम नेपा कारखाना है और जो बरहानपुर के पास है । दूसरे भी कारखाने वहां पर राज्य सरकार की राय से जो वे बतायेंगे, स्थापित करने

की बात सोची जा सकती है। दियासलाई वगैरह का भी कारखाना शायद बन पायेगा। सूचना आने पर मैं विस्तृत ब्यौरा दूंगा।

श्री पाराशर : इस सर्वे में यह दृष्टिकोण भी क्या रखा जायगा कि किसानों को कृषि के लिये और जनता को जलाने के लिये जितनी लकड़ी की आवश्यकता है उतनी को अलग से छोड़ कर राष्ट्रीय वन सम्पदा की राष्ट्रीय विकास के लिये अलग कर दिया जाय, उतना क्षेत्र अलग कर दिया जाय जैसे और मुल्कों में भी होता है ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य महोदय को इस कठिनाई को जानना चाहिये कि किसान यहां ३५ करोड़ के करीब हैं और उनको चाहे हल के लिये, चाहे छप्पर के लिये, चाहे खटिया के लिये और चाहे दातुन के लिये लकड़ी की जरूरत होती है। इनके लिये अलग जंगल छोड़ दें और बाकी जंगलों को राष्ट्रीय जंगल बनायें, मेरी समझ में वह सम्भव नहीं होगा। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है और माननीय सदस्य वहां से आते हैं, वहां जंगल के नजदीक जो लोग रहते हैं या जंगलों में जो लोग रहते हैं, निस्तार राइट उन लोगों को है, उसको देख कर चला जा रहा है।

Cost of Production of Agricultural Commodities

+

*715. **Shri Shree Narayan Das:**
Shri D. D. Puri:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri S. N. Chaturvedi:
Shri D. J. Naik:
Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any proposal for expanding the scope of cost of production studies to provide necessary data for determining the minimum prices of agricultural commodities has been finalised; and

(b) if so, the important features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). A proposal for conducting, on an extended basis, farm management studies which would provide, *inter alia*, information on cost of production of principal crops is under consideration. Such information is likely to be useful for the consideration of price policy as well as other related agricultural policies.

Shri Shree Narayan Das: How long will it take the Government to come to a final decision with regard to this?

Dr. Ram Subhag Singh: When I said in the main reply that it is under consideration, it does not mean that we have not yet started the thing. We have already taken up this matter at the official level and farm management studies are being conducted. Some reports have also been published. Besides, we set up a committee under the chairmanship of the Secretary, Agriculture, and that committee is examining the whole question as to how best to study the cost of production of different crops and what type of new machinery should be set up.

Shri Shree Narayan Das: May I know whether the whole question is being dealt with by the Directorate of Economics and Statistics or whether the co-operation of other non-official bodies, like, the Institute of Economic Growth and other organisations is being taken up by the Government in this matter?

Dr. Ram Subhag Singh: When we set up this committee under the chairmanship of the Agriculture Secretary we invited the representatives of the Statistics Division of the Planning Commission, Cabinet Secretariat as well as of the Agricultural Research Statistics Institute. It was our intention also to take the co-operation of other non-official bodies, but at that